(घ) यदि हां, तो अभी तक राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करने का क्या आधार रहा है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य प्रशासनों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाई जाने वाली आबादी, राशन कार्डों के लिए पात्रता के मानदण्ड, उचित दर की दुकानें खोलने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की हवादारी की मात्रा आदि के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुल राशन कार्डों की संख्या 14 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है खाद्यान्न के कुल अनुमानित 1700–1800 लाख मी. टन के उत्पादन में से सार्वजनक वितरण प्रणाली के लिए उसकी अधिप्राप्ति आमतौर पर 170–200 लाख मी. टन वार्षिक के बीच होती है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा थोक में किया जाता है और यह राज्य की आबादी पर आधारित नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का आबंटन, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा मौसम-जन्यकारों आदि ध्यान में रखते हुए, मासिक आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के हैं और ये किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

Persons excluded from PDs network

667. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 679 given in the Rajya Sabha on dated the 1st March, 1993 and state:

(a) whether affluent farmers who are exempted from payment of income-tax will continue availing facilities under Public Distribution System;

(b) whether Government are also considering exclusion of persons having more than two children from Public Distribution System; and

(c) if so, whether this Scheme will be restricted to only newly married persons ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) A Committee of State Ministers of Food & Civil Supplies has been set up to make recommendations for evolving a National Policy on Public Distribution System (PDS). The Advisory Council on PDS at its 15th meeting held on 21st March, 1993 adopted a resolution to the effect that a National Policy may be evolved which should focus on the need to allocate larger and more meaningful quantities to the needy and the deserving sections of the society". The Committee would be guided by this resolution in its further consultation with the State Governments. However, eligibility criteria for issue of ration cards and the entitlements of PDS commodities are matters which are decided by the State Governments/UT Administrations. The Central Government is not considering any proposal to exclude persons having more than two children from the PDS. The question of restricting any such scheme to newly married persons does not arise.

Non-availability of kerosene in rural areas

668. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether kerosene availability in fair price shops or ration shops in rural areas

are chronically suffering due to short supplies; if so, the reasons therefor;

(b) whether there are incidents of diverting the rural area quota for black marketing if so, the State-wise details for the last one year; and

(c) what action has been taken against the retailers wholesallers and oil company distributors in such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) The allocation of Public Distribution System items, namely, foodgrains, kerosene etc., is made to States|UTs by the Central Government. The responsibility for distribution to consumers lies with the States/UT Administrations. This Ministry has been generally receiving demands requesting for increase in the allocation of kerosene for PDS. No complaint has been received to suggest that kerosene has been diverted from rural areas to other areas or for blackmarketing.

States/UTs have powers under the Essential Commodities Act and other legislations to proceed against persons indulging in violation of the relevant Control Orders in the distribution of essential commodities.

The following action has been taken by States|UTs for violation of control orders issued under the Essential Commodities Act relating to various essential items including kerosene during the year 1992 :—

No. of raids made	:	136344
No. of persons arrested	:	5186
No. of persons prosecuted	:	6067
Value of goods confiscated		Rs. 2109.78 lakhs

सार्वजनिक वितरण नीति सम्बन्धी समिति

669 **श्रीमती सुषमा स्वराज:** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1993 के दैनिक "अब्जर्वर" में "पैनल टू*पुअर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने के लए समुचित सुझाव देने के हेतु कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और समिति से किन-किन मुद्दों पर विचार करने के बाद सुझाव देने के लिए कहा गया है; और

(घ) क्या उक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित न करने के क्या कारण है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालूद्दीन अहमद : (क) जी हां। (ख) जी हां।

(ग) समिति के सदस्य इस प्रकार है :—

(1) श्री जी. विश्वनाथन — अध्यक्ष
खाद्य और सहकारिता मंत्री,
तमिलनाडु सरकार।

(2) श्री नरेन डे, — सदस्य
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री,
पश्चिम बंगाल सरकार।

(3) श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, — सदस्य
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री
हरियाणा सरकार।

समिति को कोई विशिष्ट मुद्दे नहीं दिए गए है, जिन

*स्टडी लिमिटिंग पी. डी. एस. बेनिफिट्स टू